

बैठक

नए सत्र से एलएलबी ऑनर्स तीन वर्ष, बीए एलएलबी ऑनर्स पांच वर्षीय कोर्स होंगे उपलब्ध

# सीआरएसयू में जल्द शुरू होगा एलएलबी कोर्स

- बीकॉम और बीबीए चार साल की स्कीम और सिलेबस पारित किया
- सीआरएसयू की अकादमिक परिषद की 18वीं बैठक में दी मंजूरी

हरिभूमि न्यूज ▶▶ जींद



जींद। बैठक की अध्यक्षता करते हुए वीसी डा. रणपाल।

फोटो: हरिभूमि

एलएलबी करने के इच्छुक छात्रों को अब जींद से बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। नए सत्र से चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में एलएलबी ऑनर्स तीन वर्षीय और बीए एलएलबी ऑनर्स पांच वर्षीय कोर्स उपलब्ध होंगे। इसे लेकर सीआरएसयू की अकादमिक परिषद की 18वीं बैठक में मंजूरी दे दी गई है।

मंगलवार को चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में अकादमिक परिषद की 18वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न एजेंडों पर चर्चा की गई। बैठक में नए अकादमिक सत्र से एलएलबी ऑनर्स तीन साल और बीए एलएलबी ऑनर्स पांच साल को

शुरू करने का विचार और अनुमति प्रदान की गई। विश्वविद्यालय कुलपति डा. रणपाल सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार के उच्च शिक्षा विभाग यूजीसी की गाइडलाइन के अनुरूप द्वारा शिक्षकों की भर्ती और प्रमोशन के लिए यूजीसी रेगुलेशन 2018 को पारित किया है।

## बीकॉम और बीबीए चार साल की स्कीम और सिलेबस पारित किया

विभिन्न विभागों में अतिरिक्त सीटें एडमिशन के लिए बढ़ाई गई थी, उनको भी पारित किया गया। अभी भी इसी सत्र से शुरू होने वाले बीकॉम और बीबीए चार साल की स्कीम और सिलेबस को पारित किया गया। पीएचडी ऑर्डिनेंस को भी पारित किया गया। कंप्यूटर साइंस विभाग के पीएचडी कोर्स वर्क की स्कीम और कोर्स को भी पास किया गया।

## बैठक में यह रहे मौजूद

बैठक में विश्वविद्यालय कुलसचिव प्रो. लखलौन मोहन, डीन अकादमिक अफेयर्स प्रो. एसके सिन्हा, डीन ऑफ कॉलेज डा. आनंद कुमार, डीन फैकल्टी डा. कुलदीप नारा, डा. सुनील फौगाट, डा. जसवीर सिंह, डा. विशाल वर्मा, डा. अजमेर सिंह, सीपीडीएचई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से प्रो. गीता सिंह, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बठिंडा पंजाब से प्रो. वीके गर्ग, डिपार्टमेंट ऑफ कम्प्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी जीजेयू हिसार से प्रो. विक्रम कौशिक, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला प्रो. निशाज सिंह मौजूद रहे।

# सीआरएसयू : नए सत्र से एलएलबी बीए एलएलबी ऑनर्स कोर्स होंगे शुरू विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की 18वीं बैठक में प्रस्ताव को दी गई मंजूरी

संवाद न्यूज एजेंसी

जींद। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में एलएलबी ऑनर्स तीन वर्षीय और बीए एलएलबी ऑनर्स पांच वर्षीय कोर्स नए सत्र से उपलब्ध होंगे। सीआरएसयू की अकादमिक परिषद की 18वीं बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई है।

चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में अकादमिक परिषद की 18वीं बैठक मंगलवार को हुई। इसमें नए अकादमिक सत्र से एलएलबी ऑनर्स तीन साल और बीए एलएलबी ऑनर्स पांच साल को शुरू करने का विचार कर अनुमति प्रदान की गई। कुलपति डॉ. रणपाल सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार के उच्च शिक्षा विभाग यूजीसी की गाइडलाइन के अनुरूप द्वारा शिक्षकों की भर्ती और प्रमोशन के लिए यूजीसी रेगुलेशन 2018 को पारित किया गया है। बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान



सीआरएसयू की अकादमिक परिषद की 18वीं बैठक में मौजूद कुलपति और अन्य। संवाद

आयोग में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों व अकेडमी स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम मानक एवं उच्च शिक्षा मानकों का आधार विनियम 2018 पठनीय वह संशोधित माने जाएं, उसको अकादमिक परिषद की बैठक में पारित किया गया है। विभिन्न विभागों में

अतिरिक्त सीटें एडमिशन के लिए बढ़ाई गई थी, उनको भी पारित किया गया। अभी भी इसी सत्र से शुरू होने वाले बीकॉम और बीबीए चार साल की स्कीम और सिलेबस को पारित किया गया। पीएचडी ऑर्डिनंस को भी पारित किया गया। कंप्यूटर साइंस विभाग के पीएचडी

कोर्स वर्क की स्कीम और कोर्स को भी पास किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय कुलसचिव प्रो. लवलीन मोहन, डीन एकेडमिक अफेयर प्रो. एसके सिन्हा, डीन ऑफ कॉलेज डॉ. आनंद कुमार, डीन फैकेल्टी डॉ. कुलदीप नारा, डॉ. सुनील फौगाट मौजूद रहे।

## धर्म • समाज • संस्था • सिटी स्पोर्ट्स

# सीआरएसयू • अकादमिक परिषद की 18वीं बैठक में दी गई नए कोर्स की मंजूरी नए सत्र से शुरू होंगे एलएलबी ऑनर्स तीन वर्षीय व बीए एलएलबी ऑनर्स 5 वर्षीय कोर्स

भास्कर न्यूज़ | जींद

चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में अकादमिक परिषद की 18वीं बैठक आयोजित की गई। इसमें विभिन्न एजेंडों पर चर्चा की गई। बैठक में नए अकादमिक सत्र से एलएलबी ऑनर्स 3 साल और बीए एलएलबी ऑनर्स 5 साल को शुरू करने का विचार और अनुमति प्रदान की गई। विश्वविद्यालय कुलपति डॉ. रणपाल सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार के उच्च शिक्षा विभाग यूजीसी की गाइडलाइन के अनुरूप द्वारा शिक्षकों की भर्ती और प्रमोशन के लिए यूजीसी रेगुलेशन 2018 को पारित किया गया है। बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों व एकेडमी स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम मानक एवं उच्च शिक्षा मानकों का आधार विनियम 2018



जींद, सीआरएसयू में आयोजित बैठक में भाग लेते सदस्य।

पठनीय वह संशोधित माने जाएं उसको अकादमिक परिषद की बैठक में पारित किया गया।

विभिन्न विभागों में अतिरिक्त सीटें एडमिशन के लिए बढ़ाई गई थी, उनको भी पारित किया गया। अभी भी इसी सत्र से शुरू होने

वाले बीकॉम और बीबीए 4 साल की स्कीम और सिलेबस को पारित किया गया। पीएचडी ऑर्डिनंस को भी पारित किया गया। कंप्यूटर साइंस विभाग के पीएचडी कोर्स वर्क की स्कीम और कोर्स को भी पास किया गया। विश्वविद्यालय

कुलसचिव प्रोफेसर लवलीन मोहन ने बैठक में पहुंचने के लिए अकादमी परिषद के सभी सदस्यों का धन्यवाद किया।

इस मौके पर डीन एकेडमिक अफेयर प्रोफेसर एसके सिन्हा, डीन ऑफ कॉलेजेज डॉ. आनंद कुमार, डीन फैकल्टी डॉ कुलदीप नारा, डॉ. सुनील फोगाट डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, डॉ. जसवीर सिंह, डॉ. विशाल वर्मा, डॉ. अजमेर सिंह, प्रोफेसर गीता सिंह सीपीडीएचई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, प्रोफेसर वीके गर्ग सेंट्रल यूनिवर्सिटी बठिंडा पंजाब, प्रोफेसर विक्रम कौशिक डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी जीजेयू हिसार, प्रोफेसर निशान सिंह डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला मौजूद रहे।

फिर भी परिषद बैठक में लगाई अहम एजेंडों पर मोहर

# कम बजट, स्थाई भर्ती के लिए छोटा दिल

जींद, संजय शर्मा (पंजाब केसरी): सूबे का फाइनेंस विभाग भले ही बजट के मामले में जींद के चौ. रणबीर सिंह विश्वविद्यालय को एक आंख से देख रहा हो, किंतु क्षेत्र के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा की राह किसी तरह तैयार हो जाएं, इसके लिए विश्वविद्यालय में ड्यूटी जमाने वाले अपनी कवायद को निरंतर गति दे रहे हैं। भले ही सरकार स्थाई भर्ती के लिए बड़ा दिल नहीं दिखा रही हो, किंतु इन नियुक्तियों के लिए योग्य बनाने की खातिर उच्च स्तर की शिक्षा पाने के दरवाजे खोले जा रहे हैं। इसी के नतीजन मंगलवार को विश्वविद्यालय में अकादमिक परिषद की बैठक में विभिन्न एजेंडों पर चर्चा हुई, वहीं शिक्षा से जुड़े अहम मसलों पर मोहर लगाई गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय कुलपति डॉ. रणपाल सिंह ने बताया कि इस बैठक में हरियाणा सरकार के उच्च शिक्षा



अकादमिक परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए वीसी डॉ. रणपाल सिंह और मौजूद सदस्य।

विभाग यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुरूप शिक्षकों व एकेडमी स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम मानक एवं उच्च शिक्षा मानकों का आधार विनियम 2018 पठनीय वह संशोधित माने जाए को पारित किया गया है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में बढ़ाई गई अतिरिक्त एडमिशन सीटे,

इसी सत्र से शुरू होने वाले बीकॉम और बीबीए 4 साल की स्कीम और सिलेबस, पीएचडी ऑर्डिनेंस, कंप्यूटर साइंस विभाग के पीएचडी कोर्स वर्क की स्कीम और कोर्स शुरू करने, नए अकादमिक सत्र से एलएलबी ऑनर्स 3 साल और बी. ए. एलएलबी ऑनर्स 5 साल को

60 हजार छात्र जुड़े, 45 का ही स्थाई स्टाफ

जिस सीआरएसयू से 60 हजार छात्र जुड़े हैं, उसमें फिलहाल 25 नॉन टीचिंग स्थाई, 6 नॉन टीचिंग डैपुटेशन, स्थाई टीचर 20, डैपुटेशन पर एक, कान्ट्रैक्ट टीचर 34 और आऊटसोर्स पोलिसी के माध्यम से 307 कर्मचारी ड्यूटी दे रहे हैं। पिछले माह गिने-चुने शिक्षकों की भर्ती के लिए सरकार ने झंडी दी थी। किंतु लगभग एक दर्जन शिक्षकों की स्थाई भर्ती के ग्रीन सिग्नल से सीआरएसयू गुलजार होती हुई नजर नहीं आ रही।

शुरू करने का विचार और अनुमति प्रदान की गई। विश्वविद्यालय कुलसचिव प्रोफेसर लवलीन मोहन ने बैठक में पहुंचने के लिए अकादमी परिषद के सभी सदस्यों का आभार जताया।



# शिक्षकों की स्थाई भर्तियों के लिए पीएचडी अनिवार्य



सीआरएसयू की अकादमिक परिषद की बैठक में मौजूद वीसी और सदस्य। • विज्ञप्ति

**जागरण संवाददाता, जींद :** चौ. रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में मंगलवार को अकादमिक परिषद की 18वीं बैठक वीसी डा. रणपाल सिंह की अध्यक्षता में हुई। जिसमें विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में शिक्षकों और एकेडमी स्टाफ की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के रेगुलेशन 2018 के तहत न्यूनतम मानक एवं उच्च शिक्षा मानकों के आधार पर करने का प्रस्ताव पारित किया गया। अब तक प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों

## सीआरएसयू की अकादमिक परिषद की बैठक में कई प्रस्ताव पास

की भर्ती यूजीसी के रेगुलेशन 2011 को अपनाया जा रहा था। प्रदेश सरकार के निर्देश पर अब भविष्य में विश्वविद्यालयों में होने वाली शिक्षकों की भर्ती यूजीसी के रेगुलेशन 2018 के तहत होगी।

जिसके तहत अब विश्वविद्यालय में शिक्षकों की स्थाई भर्ती के लिए पीएचडी अनिवार्य कर दी

गई है। अब तक जो भर्तियां होती थी, उनमें आवेक का पीएचडी होना अनिवार्य नहीं था, पीएचडी के कुछ अंक निर्धारित होते थे

वहीं विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए बढ़ाई अतिरिक्त सीट एडमिशन के लिए बढ़ाई गई थी, उसका प्रस्ताव भी बैठक में पारित किया गया। इसी सत्र से शुरू होने वाले बीकाम और बीबीए चार साल की योजना और सिलेबस को पारित किया गया। पीएचडी अध्यादेश का भी पारित किया गया।